Sugar Cess Fund for Modernising Sugar Industry

3077. SHRI M.V. CHANDRA-SHEKHARA MURTHY :
SHRI B.V. DESAI :

Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state :

(a) whether a Rs. 80 crore sugar cess fund has been constituted for modernising sugar factories and to revive sick units in the country ;

(b) if so, the particulars of the factories that will be undertaken for modernising from this fund ; and

(c) how many of the sick units in the country have so far been provided funds out of it ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (DR. M.S. SANJEEVI RAO) : (a) Out of the amount of cess levied and collected under the Sugar Cess Act, 1982, a sum of Rs. 68 crores has been credited to the Fund set up under the Sugar Development Fund Act, 1982 for the purpose, inter-alia, of advancing loans to sugar mills for rehabilitation and modernisation.

(b) The Sugar factories which are approved by the Industrial Finance Corporation of India for grant of soft loans for rehabilitation and modernisation under its Soft Loan Scheme will be considered for grant of loan assistance from the Fund to the extent of the promoters' contribution required to be provided by the factories under such scheme.

(c) The procedure for grant of assistance from the Fund having been prescribed in the Sugar Development Fund Rules published as recently as 28th September, 1983, so far no application from any sugar factory has been received for grant of loan from the Fund for rehabilitation and modernisation.

सव्देश पम्पिग योजना को स्वीकृति

3078. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के भोजपुर जिले की सव्देश पम्पिग योजना केन्द्रीय जल आयोग के कार्यालय में स्वीकृति के लिये अभी तक लम्बित पड़ी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) बिहार सरकार द्वारा हाल ही में 123.57 लाख रुपए की लागत वाली सोन पम्प नहर (संदेश) परियोजना पर आशोधित परियोजना रिपोर्ट सितम्बर, 1983 में केन्द्रीय जल आयोग को भेजी गई है। इस परियोजना की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता एवं लागत प्रभावकारिता पूर्ण रूप से स्थापित हो जाने के पश्चात् परियोजना को स्वीकृत करना संभव होगा। इस परियोजना में बिहार के भोजपुर जिले में 6123 हैक्टेयर की सिंचाई करना परिकल्पित है।

Identification of Forest Produce

3079. SHRI GIRIDHAR GOMANGO : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether his Ministry and the States have identified the forest produces ;

(b) if so, the names of the minor forest produces and major forest produces so far identified and declared by the States, States-wise ;

(c) whether his Ministry has issued policy guidelines to the States to protect the interest, of the tribals living in and around forest for the collection of minor forest produces ;

(d) if so, the names of the States and the minor forest produces therefor ; and

(e) the minor forest produces nationalised so far by the States to eliminate the exploitation of tribals by the forest contractors and lease holders, State-wise ?

THE MINISTER OF STATE IN THE

MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA) : (a) Yes, Sir. The National Commission on Agriculture have identified all the items of forest products.

(b) The major forest produce is industrial wood consisting of timber, fuelwood and pulpwood. Minor forest produce includes all items obtained from forests other than wood.

A list of the minor forest produce as classified by National Commission on Agriculture is givin below :—

(i) fibres and flosses ;

(ii) grasses (other than oil-producing), bamboos, reeds and canes ;

(iii) Essential oils ;

(iv) Oilseeds ;

(v) tans and dyes ;

(vi) Gums, resins and oleoresins ;

(vii) Drugs, spices, poisons and insecticides ;

(viii) Leaves ;

(ix) Edible products ;

(x) Lac and its products ; and

(xi) Other products.

(c) to (e). Proposals for revising the National Forest Policy are under the consideration of the Government. Policy guidelines will be issued after the Government accepts the revised policy.

According to the information available collection and trade of important items of minor forest produce like oilseeds, kendu leaves have been nationalised/given to cooperatives in all the States with sizeable tribal population.

बिहार में कृषि योग्य भूमि

3080. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में कुल कितनी भूमि कृषि योग्य है;

(ख) कितने क्षेत्र में सिंचाई होती है और कितना क्षेत्र बिना सिंचाई का है ;

(ग) सारी भूमि में कब तक सिंचाई होने लगेगी; और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस कार्य के लिए बिहार सरकार को क्या सहायता दी जा रही है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) भूमि उपयोग सम्बन्धी आंकड़े कृषि मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं तथा अद्यतन प्रकाशित किए गए आंकड़े वर्ष 1978-79 के हैं। बिहार में कृषि योग्य भूमि का कुल क्षेत्र 11760 हजार हैक्टेयर है। सिंचाई के अन्तर्गत 2960 हजार हैक्टेयर तथा बिना सिंचाई का 8800 हजार हैक्टेयर क्षेत्र है।

(ग) बिहार की अन्ततः सृजनीय सिंचाई क्षमता 12,400 हजार हैक्टेयर होने का अनुमान लगाया गया है जिसमें एक बार से अधिक सिंचित किया गया क्षेत्र भी शामिल है जबकि समस्त अन्ततः सृजनीय सिंचाई क्षमता को कब तक सृजित किया जाएगा, इसके वास्तविक अनुमान को बताना सम्भव नहीं है, फिर भी हमारे प्रयास अगली शताब्दी की शुरुआत में देश भर में अन्ततः सृजनीय क्षमता को प्राप्त करने के हैं।

(घ) सिंचाई एक राज्य विषय है तथा राज्य सरकारों द्वारा उनकी समस्त विकास योजनाओं के अन्तर्गत सिंचाई परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जाता है। केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों तथा अनुदानों के रूप में दी जाती है तथा यह किसी विशिष्ट परियोजना अथवा विकास के क्षेत्र से जुड़ी नहीं होती है।